दैनिक जागरण

Publication	Dainik Jagran (City)
Edition	Ghaziabad
Language/Frequency	Hindi/Daily
Page No	25
Date	08th February 2019

400 करोड़ से रैपिड रेल को लगेंगे पंख

प्रदेश सरकार ने पैसों का किया इंतजाम, चुनाव आचार संहिता से पहले किया जा सकता है भूमि पूजन

राज्य बजट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण को रफ्तार मिलेगी। बृहस्पतिवार को पेश हुए प्रदेश सरकार के बजट में देश के पहले रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हाल में केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) को 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इस रेल सेवा के शुरू होने से लोग मेरठ से दिल्ली 60 मिनट में पहुंच सकेंगे। गाजियाबाद से आइजीआइ एयरपोर्ट तक पहुंचने में 25 मिनट का वक्त लगेगा।

दिल्ली में सराय कालेखां से शुरू होकर गाजियाबाद के रास्ते मेरठ तक रैपिड रेल का कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर प्रस्तावित है। निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले भूमि-पूजन किया जा सकता है। पिलर खड़े करने के लिए मोहननगर में पाइल लोड टेस्ट चल रहा है। रोड चौड़ीकरण, यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम जारी है। जियो टेक्निकल जांच पूरी हो चुकी है। रास्ते में आ रहे पेड़ों को काटने की अनुमति वन विभाग प्रदान कर चुका है।

7.40 लाख यात्री करेंगे सफर : इस कॉरिडोर पर रैपिड रेल में रोजाना 7.40 लाख यात्री सफर करेंगे। एनसीआरटीसी ने सर्वे से यह आकलन किया है। इस कॉरिडोर पर रैपिड रेल के 14 स्टेशन बनेंगे। मेरठ की सीमा में आठ मेट्रो के स्टेशन बनाए जाएंगे। दोनों मिलाकर 22 स्टेशन प्रस्तावित है।

तीन जगह मेट्रो से जुड़ेगा कॉरिडोर : तीन स्थानों पर रैपिड रेल के स्टेशन मेट्रो से जुड़ेंगे। आनंद विहार, अशोक नगर और मेरठ तिराहे पर मेट्रो स्टेशन से रैपिड रेल कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। योजना है कि स्काई वॉक बनाकर मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाए। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जरूरत के हिसाब से दोनों सेवाओं का लाभ ले सकें।

प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया है। इससे निर्माण कार्य तेजी से हो सकेगा। - **सुधीर शर्मा**, जीजीएम स्ट्रैटजिक एवं सीपीआरओ, एनसीआरटीसी

अंतर-संचालित होगी रैपिड रेल

रैपिड रेल यात्रियों को एक से दूसरे कॉरिडोर पर जाने के लिए मेट्रो की तरह रेल बदलनी नहीं होगी। बार-बार रेल बदलने की झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए एनसीआरटीसी रैपिड रेल कॉरिडोर को अंतर-संचालित (इंटर ऑपरेबल) बनाएगा। जिससे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के यात्री बिना रैपिड रेल बदले पानीपत, एसएमबी (शाहजहांपुर-नीमराना-बेहरोर अर्बन कॉम्पलेक्स) और अलवर तक जा सकेंगे। रैपिड रेल कॉरिडोर को अंतर-संचालित बनाने का निर्णय हुआ है। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर की एक रैपिड रेल सीधे एसएमबी तक जाएगी। दूसरी पानीपत जाएगी। इसी क्रम में प्रत्येक 5 से 10 मिनट के अंतराल पर रैपिड रेल का संचालन होगा।

- कुल 31632 करोड़ रुपये आएगी लागत, जिसमें केंद्र 5693.76 करोड़ और प्रदेश सरकार 5915.18 करोड़ रुपये अंशदान देगी
- प्रत्येक स्टेशन के डेढ़ किलोमीटर परिधि में 713 हेक्टेयर भूमि होगी रैपिड रेल प्रभावित क्षेत्र
- रैपिड रेल में होंगे नौ कोच
- गाजियाबाद में 15,470 वर्गमी स्थाई निर्माण के लिए, 82104 वर्ग मीटर भूमि अस्थाई निर्माण के लिए चाहिए
- रेल की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगा, न्यूनतम 100 किलोमीटर
- 2024 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य
- 2054 तक लागत की होगी वसूली

दुहाई में दो स्टेशन

दुहाई और मोदीपुरम में कॉरिडोर पर बनने वाले मुख्य स्टेशन के साथ डिपो में सरफेस स्टेशन बनाए जाएंगे। डिपो कॉरिडोर से करीब एक किलोमीटर अंदर होगा। उसके आसपास रहने वाली आबादी को लाभ देने के लिए ऐसा किया जाएगा।

ये खूबियां भी होंगी

- बिजनेस क्लास कोच होगा
- प्लेटफार्म स्क्रीन डोर लगेंगे, रेल आने पर ही यह डोर खुलेंगे
- महिलाओं के लिए अलग कोच होगा

वेदर प्रूफ होगी रेल

रैपिड रेल हर मौसम में तेज रफ्तार में ट्रैक पर दौड़ेगी। एनसीआरटीसी दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के लिए वेदर प्रूफ रैपिड रेल खरीदेगा। आंधी, बारिश और कोहरे में रेल अपनी निर्धारित रफ्तार में दौड़ती नजर आएगी। भारतीय रेल की दुश्वारियों को देखते हुए वेदरप्रूफ रैपिड रेल खरीदने पर सहमति बन चुकी है।

खूबियों से लैस स्मार्ट कोच लगेंगे

रैपिड रेल में स्मार्ट कोच लगाए जाएंगे। ये कोच कई खूबियों से लैस होंगे। आगे से आकार एयरोडायनेमिक्स होगा। इसमें कई तरह के सेंसर लगे होंगे। उससे ब्रेक घिसने की जानकारी, एक्सेल का टेंप्रेचर, पहियों की कंडीशन कोच से ही नियमित रूप से रैपिड रेल कंट्रोल रूम को मिलती रहेगी। कोच के अंदर कैमरे होंगे, जिससे हर गतिविधि रिकॉर्ड होती रहेगी। हवाई जहाज की तरह आरामदायक सीटें लगी होंगी।

घटेगा 21.35 लाख टन प्रदूषण

रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रदूषण के कहर को काफी हद तक कम कर देगा। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रूट पर इसका संचालन शुरू होने से वायुमंडल में प्रतिवर्ष 21.35 लाख टन प्रदूषण तत्वों की कमी आएगी। यह दावा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) का है। इस तर्क के साथ की रैपिड रेल का संचालन शुरू होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग 37 से बढ़ कर 63 फीसद हो जाएगा। सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या घटेगी। जिससे वातावरण प्रदूषित करने वाले तत्वों में भारी कमी आएगी। एनसीआरटीसी की माने तो सबसे ज्यादा कमी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन में आएगी। जिससे लोग खुल कर सांस ले सकेंगे।

इन प्रदूषण तत्वों में आएगी वार्षिक कमी

पार्टिकुलेट मैटर	60 हजार टन
नाइट्रोजन ऑक्साइड	4,75,000 टन
हाइड्रो कार्बन	8,00,000 टन
कार्बन मोनोऑक्साइड	8,00,000 टन

इतनी घटेगी वाहनों की निर्भरता

वाहन	वर्तमान निर्भरता	आरआरटीएस संचालन के बाद उपयोग
कार	36 फीसद	22 फीसद
रेल	32 फीसद	15 फीसद
दुपहिया	27 फीसद	15 फीसद
बस	पांच फीसद	दो फीसद

मेरठ में रैपिड रेल के ट्रैक पर दौड़ेगी मेट्रो

मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच रैपिड रेल के ट्रैक पर ही मेट्रो रेल दौड़ाई जाएगी। लिहाजा इसी लाइन पर मेट्रो के लिए आठ अतिरिक्त स्टेशन बनाए जाएंगे। जिसमें परतापुर, रिठानी, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैसाली, एमईएस कॉलोनी, दौरली और मेरठ नॉर्थ शामिल हैं। पहले मेट्रो कॉरिडोर अलग बनाया जाना तय हुआ था। योजना में बदलाव कर मेट्रो रेल परियोजना पर खर्च होने वाले 6300 करोड़ रुपये राज्य सरकार के बच गए हैं।

कॉरिडोर के आसपास घर बनाना होगा महंगा

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर स्टेशनों की डेढ़ किलोमीटर की परिधि में घर, दुकान और कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स बनाना महंगा होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए एनसीआरटीसी एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेगा। उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें अंशदान देगी। इस लागत को वसूलने के लिए एनसीआरटीसी ने वेल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (वीसीएफ) के चार टूल बताए हैं। जिसमें स्टेशनों के आसपास निर्धारित परिधि में स्टांप ड्यूटी एक फीसद अधिक लेने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में स्टांप ड्यूटी भूखंड कीमत की सात फीसद ली जा रही है। जोकि, बढ़ कर आठ फीसद हो जाएगी। विकास शुल्क भूखंड क्षेत्रफल के बजाए निर्मित क्षेत्र पर लेने का सुझाव दिया है, जोकि वर्तमान दर से चार गुना अधिक होगा। यह सुझाव भी दिया गया है कि इस परिधि में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज (आइडीसी) लिया जाए, जोकि विकास शुल्क का 25 फीसद होगा। 4.0 तक एफएआर की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। जिसमें कहा गया है कि 1.5 से ऊपर एफएआर बेचा जाए।

4 स्टेशनों के पास विशेष कॉरिडोर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआइयूए) के विशेषज्ञों ने एनसीआरटीसी को गाजियाबाद में गुलधर स्टेशन के आसपास वेयरहाउस और हरित औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का सुझाव दिया है। हरित औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे उद्योग लगाने के लिए कहा गया है, जिससे प्रदूषण न फैले। दुहाई डिपो के पास आवासीय कॉलोनी और ऑफिस स्पेस बनाने का सुझाव दिया है। वहीं मेरठ क्षेत्र में परतापुरम के पास औद्योगिक और मोदीपुरम में शैक्षणिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना है।

संबंधित खबरें पेज >> III